

भारत सरकार  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.4778  
दिनांक 23 मार्च, 2020  
हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं

4778. डॉ. के. जयकुमार:  
डॉ. टी.आर. पारिवेन्द्र:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) डेल्टा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के क्रयान्वयन के लिए अधग्रहित की गई कृषि भूमि की कुल मात्रा कितनी है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को लागू करके कृषि फसलों/उत्पादों संबंधी संभावित साइड-इफेक्टों और हानियों का डेल्टा क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का लोगों के संदेहों और भय को दूर करने के लिए हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं संबंधी श्वेत पत्र की घोषणा करने का वचन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) तमलनाडु में स्थापित की जाने वाली हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं कौन सी हैं;
- (ङ) इन परियोजनाओं के आरंभ होने से पहले प्राप्त की जाने वाली परियोजना-पूर्व स्वीकृति का ब्यौरा क्या है; और
- (च) तमलनाडु परियोजनाओं के लिए इन स्वीकृतियों की स्थिति क्या है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने आन्ध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में कृष्णा गोदावरी बेसिन परियोजना के तहत एक अन्वेषण कूप के वेधन के लिए 8.19 एकड़ पैमाइश की कृषि भूमि का एक भू-खंड खरीदा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने कावेरी परिसंपत्ति में स्थायी आधार पर 47.18 एकड़ और अस्थायी आधार पर 1728.73 एकड़ भूमि का अधग्रहण किया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन (राजामुंदरी परिसंपत्ति) के तहत सीमान्त क्षेत्रों और आधार कार्यालय/कार्यशाला इत्यादि के लिए स्थायी रूप से अधग्रहीत भूमि सहित ओएनजीसी के प्रचालनों के लिए अस्थायी रूप से कुल अधग्रहीत भूमि 2692.324 एकड़ है।

(ख) और (ग) अन्वेषण और उत्पादन गति व धर्याँ न केवल डेल्टा क्षेत्र में अपितु देश के अन्य भागों में भी कृषि के साथ सहअस्तित्व में रहती हैं। हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण और उत्पादन गति व धर्याँ के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी सां व धक दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अनुपालन करना होता है। इन मंजूरियों को व भन्न प्रा धकारियों से प्राप्त किया जाता है। प्रचालक अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्य तभी शुरू कर सकता है जब सभी सुसंगत

अनुमोदनों को प्राप्त कर लिया जाए। इसके अलावा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), 50 वर्षों से सुसंगत अनुमोदनों को प्राप्त करने के बाद डेल्टा क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन गति व धर्यों को निष्पादित कर रहा है।

(घ) और (च) वर्ष 2019-20 के दौरान तमलनाडु राज्य में प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न लखत है -

| ओएएलपी दौर | ब्लॉक का नाम           | कंपनी                        | क्षेत्रफल (वर्ग कमी में) | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | कुल/राज्य-वार क्षेत्रफल (वर्ग कमी में) | जिला               |
|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| II         | सीवाई-ओएनएचपी-2018/1   | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ल मटेड | 474.20                   | तमलनाडु                      | 474.2                                  | नागपिनम, तिरुवरूर  |
| III        | सीवाई-ओएनएचपी - 2018/2 | ओएनजीसी                      | 459.83                   | तमलनाडु                      | 386.53                                 | कुड्डालोर, नागपिनम |
|            |                        |                              |                          | पुडुचेरी                     | 73.30                                  | कराईकल             |
| III        | सीवाई-ओएनएचपी - 2018/3 | ओएनजीसी                      | 1403.40                  | तमलनाडु                      | 1259.43                                | शवगंगा, रामनाथपुरम |
|            |                        |                              |                          | अपतटीय                       | 143.97                                 | -                  |

केन्द्र सरकार ने अपतट क्षेत्रों के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएलस) प्रदान किया है, कन्तु अभतट क्षेत्रों के संबंध में तमलनाडु सरकार द्वारा अभी तक उक्त लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(ड.) हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को शुरू करने से पहले पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न लखत मंजूरी प्राप्त की जाती है -

- I. पर्यावरण संबंधी मंजूरी;
- II. वन संबंधी मंजूरी (एफसी) यदि परियोजना में वन भूमि का वपथन शामिल है;
- III. वन्यजीवन संबंधी मंजूरी (डब्ल्यूएलसी) यदि परियोजना संरक्षित क्षेत्र (अभ्यारण, राष्ट्रीय पार्क इत्यादि) के पर्यावरणीय संवेदनशील जोन के दायरे में आती है;

- IV. तटवर्ती वनियामक जोन (सीआरजेड) मंजूरी यदि परियोजना सीआरजेड क्षेत्र के दायरे में आता है;
- V. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति और प्रचालन संबंधी सहमति।

\*\*\*\*